LOK SABHA

Friday, June 30, 1967/Asadha 9, 1889 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

OBITUARY REFERENCE

Mr. Speaker: I have to inform the House of the sad demise of Shri Gopinath Singh, who passed away at Lucknow on the 29th June, 1967, at the age of 75

Shri Gopinath Singh was a Member of the Provisional Parliament during the years 1950-52.

We deeply mourn the loss of this friend and I am sure the House will join me in conveying our condolences to the bereaved family.

The House may stand in silence for a short while to express its sorrow.

The Members then stood in silence for a short while

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ढांचा निर्माण उद्योग

\+

*841. श्री रवि राय :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री एस० एम० जोशी :
श्री मधु लिमये :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इंजीनियरी संस्था (इंडियन इंजीनियरिंग एसोसिएशन) द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार ढांचा (स्ट्रक्चरल) निर्माण उद्योग की आधी क्षमता का भी उपयोग नहीं किया जा रहा है,

(ख) क्या सरकार का विचार विदेशी सहयोग से सरकारी क्षेत्र में ऐसे अनेक बड़े कारखाने स्थापित करने का है, और

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र की पूरी क्षमता का उपयोग करने के उद्देश्य से इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) अगस्त, 1966 में इंडियन इंजीनियरिंग एसोसिएशन ने ढांचा निर्माण उद्योग की फालतू क्षमता के बारे में अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि पिछले वर्ष इस उद्योग को कोई बड़े आर्डर नहीं दिये गये थे और उस उद्योग के अधिकांश एकक अपनी क्षमता का 60 प्रतिशत उत्पादन कर

रहे थे । फिर भी सरकार द्वारा किये गये निर्धारण के अनुसार फालतू क्षमता मुख्य रूप से उन एककों के सम्बन्ध में है जो हल्के ढांचे बनाते हैं और उस क्षमता के बारे में ही जो मध्यम तथा भारी ढांचे बनाने के लिये उपलब्ध है और जिसका अपेक्षाकृत अधिक अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है ।

(ख) भारी ढांचे बनाने का एक एकक उत्तर प्रदेश के नैनी में स्थापित किया जा रहा है जिसकी वार्षिक क्षमता 25,000 टन होगी । यह एकक भारत सरकार और आस्ट्रिया के मैसर्स वॉयस्ट का एक मिला जुला उद्यम होगा और इसमें अतिरिक्त एक ढांचा निर्माणशाला की भी स्थापना की जा रही है जिसकी उत्पादन क्षमता लगभग 30,500 मी० टन प्रति वर्ष होगी और जो सोवियत सहायता प्राप्त बोकारो इस्पात संयंत्र का एक अभिन्न अंग होगा ।

(ग) सरकारी क्षेत्र की स्वीकृत परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये उत्तरदायी कर्मी सम्बन्धित अधिकारियों को यह परामर्श दिया गया है कि वे ढांचे सम्बन्धी अपनी आवश्यकतायें शीघ्र पूरी करने के लिए इस उद्योग के विभिन्न एककों को अपने आर्डर दें । उनकी इन आवश्यकताओं की विस्तृत सूचना इकट्ठी करके ढांचा निर्माण उद्योग की नामिका को दे दिये गये हैं जिससे उद्योग इनके लिए टेंडर मांग सकें और आवश्यक प्रारम्भिक कार्य कर सकें ।

ढांचों के निर्यात के प्रश्न की भी जांच कर ली गई है । ढांचा निर्माण उद्योग की नामिका को यह परामर्श दिया गया है कि वह इंजीनियरी निर्यात संवर्द्धन परिषद् से उनके सम्बन्ध में एक दल बनाये जो विदेशों के उन बाजारों का सर्वेक्षण करे जिनका अध्ययन अभी तक नहीं किया गया है । नामिका द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है ।

निर्यात के इंजीनियरी की वस्तुएं बनाने वालों के लिए घरेलू तथा विदेशों में इस्पात और कच्चे लोहे के मूल्यों के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए संयुक्त सचिव समिति द्वारा एक योजना तैयार कर ली गई है ।

एक भारतीय कम्मोडियम की स्थापना करने के सुझाव पर भी नामिका द्वारा इस समय विचार किया जा रहा है जो विदेशों में पैकिंग की व्यवस्था और विशेष रूप से विशद परामर्श सम्बन्धी सेवा की व्यवस्था करने, ढांचे और उपकरण देने तथा बारा-बारी से एशिया और अफ्रीका में परियोजनायें बनाने और उन्हें चलाने का काम करेगा ।

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने फरमाया कि सन् 1965 के साल में 40 प्रतिशत उत्पादन इस फर्म का कम हो गया और बाद में उन्होंने बताया कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का उन्होंने परामर्श दिया है कि उनके पास जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज उनके पास आर्डर क्यों देंगे तो मैं जानना चाहता हूं कि सन् 1965 के साल में जो 40 प्रतिशत कमी है उस के लिए कौन जिम्मेदार है और जो जिम्मेदार इसके लिये ठहराये जायेंगे उन के लिये क्या मंत्री महोदय फरमायेंगे कि उनको दंड मिलेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : जैसा कि अमोलसंयम ने कहा कि उन की राय में 60 परसेंट घटा है लेकिन मैंने जैसा जवाब में बतलाया है जहां तक उनकी रिपोर्ट का ताल्लुक है उन्होंने हैवी, मीडियम और लाइट स्ट्रक्चरल्स सब का हिसाब लगा कर 60 परसेंट कहा है । हमारी जो इन्फीरमेशन है उससे यह मालूम होता है कि जहां तक हैवी इंडस्ट्रीज का ताल्लुक है उन में उतनी कमी नहीं है सिर्फ लाइट स्ट्रक्चरल्स में जरा सा रिडक्शन है, घटाव है । उसमें जहां तक हमारी पब्लिक इंडस्ट्रीज का

मालूम है वह ज्यादातर इस बात पर जोर दे रही है कि हैवी और मीडियम स्ट्रक्चरल्स वह किसी तरीके से यह अपने मुल्क में स्वयं बना सकें । अभी उसमें काफी कमी है । फोर्थ फाइव इयर प्लान के आखिर में काफी कमी रहेगी और उस कमी को पूरा करने के लिये ताकि हमें बाहर से ऐक्सपोर्ट न करना पड़े हम इसको बढ़ाना चाहते है और इसीलिए पबलिक सैक्टर में हेवी स्ट्रक्चरल्स के लिए प्रोजेक्ट किये गये है ।

श्री रवि राय : क्या मंत्री महोदय फरमायेंगे कि जो लाइट स्ट्रक्चरल्स है उन को रिकंडिशन कराके उन के जरिए सिंचाई के लिए जो गंगा नदी या जमुना नदी के ऊपर जो सूखी जमीन है उस जमीन के ऊपर पानी फेंकने के लिए क्या कोई कार्यक्रम मंत्री महोदय बनायेंगे ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जितने लाइट स्ट्रक्चरल्स हैं वह बहुत सी चीजें बनाते हैं बाकी सारी दिक्कत क्या है कि यह एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि रीजनल बेसिस के ऊपर नहीं हो सकती है और जो कि यूनिट के हिसाब से भी इस का लिहाज नहीं किया जा सकता । यद्यपि इस में काफी चीजें दूर ले जानी पड़ती हैं । रीजनल इम्बैलेंस का बड़ा सवाल आता है । हम यह देखते हैं कि जब तक एकोनामिक रिसैशन होगा और बहुत सारी चीजों की डिमांड नहीं होगी लाइट स्ट्रक्चरल्स को नुकसान पहुंचेगा । किसी तरीके से वह नुकसान कम हो जाए इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं । हमने अपनी तमाम पबलिक इंटरप्राईजेज से कह रखा है कि उन को किन किन चीजों की जरूरत है उस का वह ऐस्टिमेट करें और ऐस्टिमेट करके उन लोगों को बतायें ताकि वह आर्डर वगैरह के लिए इंडेंट वगैरह दे सकें ।

श्री एस० एम० जोशी : क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि जो कैपेसिटी अब काम में नहीं आती है वह सारी ही लाइट स्ट्रक्चरल्स के बारे में है या हैवी के बारे में भी कैपेसिटी आइडिल है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : ज्यादातर लाइट स्ट्रक्चरल्स की है, हैवी की बहुत कम है और जैसा कि मैंने पहले बतलाया वह ऐसी है कि जिसकी वजह से हमें कोई अंदेशा नहीं है । वह जल्दी पूरी हो सकती है क्योंकि अभी बोकारो स्टील प्लांट के लिए जो हमने तस्फिया किया है उस में काफी आर्डर्स के लिए लोगों को इत्तिला दे दी गई है और वह लोग लैटर आफ इंडैंट वगैरह भेजेंगे ।

Shri Sradhakar Supakar: The main question has not been answered although the statement is long. The main question relates to the steps taken by the Government in the matter in order to make use of the full capacity of the private sector. What has the government done to see that full capacity is utilised? It says here that so far as heavy structurals are concerned, export promotion is being encouraged. So far as light structurals are concerned, what is the government doing in order to make full utilisation of the entire capacity?

Shri F. A. Ahmed: As I have already indicated by its very nature this industry is of a kind where we cannot expect to say that it will be working to its full installed capacity. But it is certainly true that there has been a fall in the demand for light structurals due to various factors. There has been a recession particularly on account of less demand from the railways for wagons.

Shri Sradhakar Supakar: Is it a temporary recession?

Shri F. A. Ahmed: This matter was brought to the notice of government and we have taken action in various directions so that where posi-

ble the gap is reduced. We have asked the public sector undertakings to sit down and prepare an estimate of of their requirements in the coming few years and that is notified to these people so that they may take action for placing order. We are also trying to export structural manufactures here and for that we subsidise the gap between the domestic and the international prices. All efforts are made to export more and to give to these people all the necessary assistance.

Shri Hem Barua: There is a lot of idle capacity in our engineering industry and yet enormous quantities of engineering goods are imported into this country In that context, how does the government propose to explain this paradoxical situation?

Shri F. A. Ahmed: That is being looked into Whatever is being manufactured by these three types of structurals is not being allowed to be imported from outside.

Shri Hem Barua: If I say that this is not a reply to my question, Sir, you would say that I am beating about the bush, you might say so. But in your wisdom would you please tell us whether this is a reply to my question?

Shri F. A. Ahmed: Recession has taken place because of certain reasons. These structurals are to be divided into three categories· heavy, medium and light I have got reports to indicate that the gap in respect of heavy structurals is not big There is a big gap so far as light structurals are concerned due to the economic recession, because of the lack of orders from various quarters. It has not been on account of the fact that we have allowed the import of these light structurals from outside

श्री लिंगेश्वर प्रसाद : जो बयान दिया गया है उसमें यह बतलाया गया है कि सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये उत्तरदायी सभी सम्बन्धित अधिकारियों को यह परामर्श दिया गया है कि वे ढांचे सम्बन्धी अपनी आवश्यकतायें शीघ्र पूरी करने के लिए इस उद्योग के विभिन्न एककों को अपने आर्डर दें। मैं जानना चाहता हूं कि इंडस्ट्रियल एस्टेट्स से लेकर जो भी सरकारी कारखाने हैं उन कारखानों को सरकार के जो दूसरे विभाग हैं वह कितने आर्डर देते है ? इस सर्कुलर के बाद क्या मिनिस्ट्री ने इस बात की कोई जांच की है ? अगर की है तो उस के सम्बन्ध में क्या कोई विवरण मंत्री महोदय सदन पटल पर रखेंगे ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहां तक उन मिनिस्ट्रीज का ताल्लुक है जो यह चीजें इम्पोर्ट करती है, सब के साथ कान्फरेंस हुई थी और उसके बाद एक कमेटी बनाई गई। उसके बाद यह तय हुआ कि उन लोगों को किन किन चीजों की जरूरत है इसकी इत्तिला वह इस कमेटी को देंगे। इत्तिला मिलने के बाद यह कमेटी इंडस्ट्रीज से कहेगी कि इन चीजों की जरूरत है पब्लिक अन्डरटेकिंग्स से और वह जिस तरह से भी हो उन से कन्टेक्ट करे और उनको तमाम चीजें पहुंचाने की कोशिश करे।

Shri N. K. Somani: In view of the development of the public sector projects in the heavy structural industry, it will be very easy to convert them into light and medium industry also May I know what is the policy of the Government in such a case, because that will be detrimental to hundreds of units all over India in the private sector?

Shri F. A. Ahmed: I have said that the Government's intention is to help the private sector as far as possible so far as the idle capacity is concerned. The report submitted by the Engineering Association gives the over all picture that they have been working to the extent of 60 per cent of their capacity taking into consideration the manufacture of heavy, medium and light structurals. Also, they have

taken into consideration the manufacture of all the units. But the hon. member knows that some of these units actually last year manufactured much more than in the previous year, while there were certain units which manufactured much less than what they manufactured in the year privious to that. The industry is of such a nature that we cannot assure the order unitwise. It will have to depend on the region where these things are required and how far these things have to be carried from one place to another. So far as heavy structurals are concerned, the difficulties which have been placed before me are that atually we are supplying less than the demand for those structurals and by the end of the fourth plan, there will be a shortage even after what we will be manufacturing in the three or four projects which have been taken up in the public sector. So far as light structurals are concerned, it is true that there has been idle capacity and for that purpose, we have been constantly meeting all those persons who represent the private industry to see how we can help them.

Mr. Speaker: If for every supplementary the whole policy is given out, only one question can be answered in the whole day.

Shri N. K. Somani: He has not given the answer to my question.

Mr. Speaker: Everybody says like that. Next question.

मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी

+

*842. **श्री क० ना० तिवारी :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी को दिये गये ठेके की अवधि को पुनः बढ़ाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Parimal Ghosh): (a) and (b). Since provision existed in the previous agreement with M|s. A.H. Wheeler and Co. for its automatic renewal for a further period provided the service rendered was satisfactory, their contract has been renewed with effect from 1-1-1967.

श्री क० ना० तिवारी : कितने दिनों के लिये यह रिन्यूअल हुआ है ?

Shri Parimal Ghosh: The contract has been renewed from 1-1-1967 till 31st December, 1975 for a period of 9 years.

श्री क० ना० तिवारी : इस के पहले यह हाउस डिमांड कर रहा था कि व्हीलर का जो कंट्रैक्ट है उसे खत्म कर दिया जाये और सरकार यह कहती थी कि चूंकि कंट्रैक्ट है इसलिये खत्म नहीं किया जा सकता है । क्या कारण है कि व्हीलर को फिर कंट्रैक्ट दिया गया है जब कि दूसरे लोग इस कंट्रैक्ट को चाहते थे ?

Shri Parimal Ghosh: Sir, till 1960 it is a fact that there has been a concentration of quite a number of shops so far as Wheeler & Co., were concerned. The matter was reviewed in the year 1960 and in order to break that concentration it was decided that the agreement would be renewed only for a period of 5 years. After that there has been a representation from Wheeler & Co. and the representation was that because of not having the renewal clause there has been a certain amount of uncertainty in the matter of establishment and their staff. The matter was then reviewed and in consultation with the Ministry of Law it was decided that they will be given 5 years with a renewal option for another 5 years. After the expiry of the first 5 years when the